ancillaries etc. the effect of any specific brand name has not been studied. There is scope for expansion of this industry in the country.

(d) The growth rate of the industry as per information furnished by DGTD works out to be approximately 2.5 per cent per annum between 1981—1985 and whereas the same is approximately 5.5 per cent per annum between 1986—1990.

Addition of colour in Amul Butter

725. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state what are the reasons for permitting addition of colour in Amul Butter and refusing the same in Dalda Vanaspati Ghee?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): As per Directorate General of Health Services, Government of India, in Amul Butter which is a table butter, two natural colours, namely, Annatto and Carotene are permitted as per International practice. But in the case of Vanaspati addition of colouring matter is neither practicable nor desirable.

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों का पुनर्गठन किया जाना

726. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों को उनमें भारी पूंजी निवेश के बावजूद लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योगों के मुकाबले में वाणिज्यिक रूप से प्रतियोगी सिद्ध नहीं हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निजी क्षेत्र के एकक निरंतर लाभ कमाते आ रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दोनों क्षेत्र के उद्योगों के संचालन, कार्यकरण, प्रशासन, उत्पादन कुशलता और बिक्री आदि का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ; और

(ङ) क्या सरकार बदलती हुई अर्थ-मान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का पुनर्गठन करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) वर्ष 1989-90 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 98 उद्यमों ने 1959.09 करोड़ रुपये का कुल घाटा उठाया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को संसद में प्रस्तुत औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करने के लिए उपायों की घोषणा पहले ही कर दी है ।

727. [*Transferred to the 3rd December*, 1991]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहकारी समितियों को सौंपा जाना

728. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय रुग्ण उद्योगों को कर्मचारियों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को सौंपने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से रुग्ण उद्योगों की सहकारी समितियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने के लिये रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के मौजूदा उपबंधों में संशोधन करके सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल के पास भेजने का निर्णय किया है । इन योजनाओं को बनाने के एक भाग के रूप में मण्डल सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को उस उद्यम के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी समितियों को सौंपने का निर्णय कर सकता है ।

घटिया किस्म के पेंट के कारण मारुति कारों का अस्वीकार किया जाना

729. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में "मारुति एक्सपोर्टस स्टाल्ड बाई पूअर पेंट सप्लाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पेंट की घटिया क्वालिटी की वजह से हाल ही में निर्यात की गई अनेक मारुति कारों को अस्वीकार कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी कारें थीं तथा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण कम्पनी को कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(घ) क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो की गई इस जांच का ब्यौरा क्या है तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निर्यात के लिए निर्मित 673 कारों की पेंट की क्वालिटी में दोष का चूंकि शिपमेंट से पूर्व ही पता लग गया था, अतः ये कारें निर्यात नहीं की गई । आवश्यक मरम्मत किए जाने और पेंट के मूल आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत पूरी होने के बाद ही कम्पनी को पेंट की क्वालिटी में दोष के हुए वित्तीय घाटे का पता चल सकेगा ।

(घ) और (ङ) अन्तवर्ती पेंट की परत संतोषजनक न होने से ऊपरी परत के चिपकाव में कमी के कारण दोष उत्पन्न हो गया था । घाटे के सम्बन्ध में पेंट के आपूर्तिकर्ता से बातचीत की जायेगी

New sugar factories in Andhra Pradesh

730. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of licences proposed to be issue for new sugar factories in Andhra Pradesh during the Eighth Five Year Plan; and

(b) the number of them proposed to be set up in the Joint Sector. Private Sector and the Co-operative Sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P J. KURIEN): (a) and (b) The revised Guidelines for licensing of new and expansion of existing sugar factories for the Sugar Year 1991-92 and the Eighth Five Year Plan have been issued by the Government vide Press Note No. 16 dated 8th November, 1991. According to the Guidelines, while granting licences for new units and expansion projects, the additional capacity to be created upto the end of the Eighth Five Year Plan will be kept in